

80



निगरानी क्रमांक

/ 2012

R - 3093 - I/12

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर म.प्र.

क्री बनक छवि नाम पात्र  
दाश प्रयुत

1. वरदीबाई बेवा रामचन्द्रजी जाट,
2. धन्नालाल पिता हीरालालजी जाट,  
निवासीयान ग्राम ढीकवा जिला रतलाम

प्रार्थीगण

विरुद्ध

R.M  
4P  
31/8/12

विरेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंहजी राजपुत,  
निवासी ग्राम ढीकवा जिला रतलाम

प्रतिप्रार्थी

निगरानी बनाराजगी न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय रतलाम ज़िला प्रक्र. 6/निगरानी/11-12 में पारित आदेश दिनांक 27.12.11 जिसके द्वारा प्रार्थीगण की निगरानी निरस्त की जाकर न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय टप्पा बिलपांक के प्रकरण क्रमांक 137/अ-12/10-11 अंतर्गत दिनांक 18.06.11 को की गई सीमांकन कार्यवाही में हस्तक्षेप किये जाने से इंकार किया गया।

2869

क्रमांक  
कृष्णपुर द्वारा उआ  
3-9-12 को प्राप्त

क्रमांक नं 2869  
निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण की और से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है—

#### प्रकरण के तथ्य

यह कि प्रतिप्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय टप्पा बिलपांक के समक्ष एक आवेदनपत्र ग्राम ढीकवा जिला रतलाम में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 223/2/2 रकबा 1.190 हैक्टर का सीमांकन अधिक्षक भूअभिलेख के माध्यम से करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिस पर से श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय बिलपांक द्वारा अपने यहां प्रकरण क्रमांक 137/अ-12/2010-11 पंजीबद्द कर सीमांकन हेतु आदेशित किया गया था। जिस आदेश के आधार पर अधिक्षक भूअभिलेख एवं पटवारी द्वारा दिनांक

2  
ग्रामपाल  
द्वारा दिनांक

(2)

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3093-एक/12

बिला - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री द्वारिकाधीश चौधरी एवं श्री महेश योगी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक ३-१-१९ को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(3) </p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	